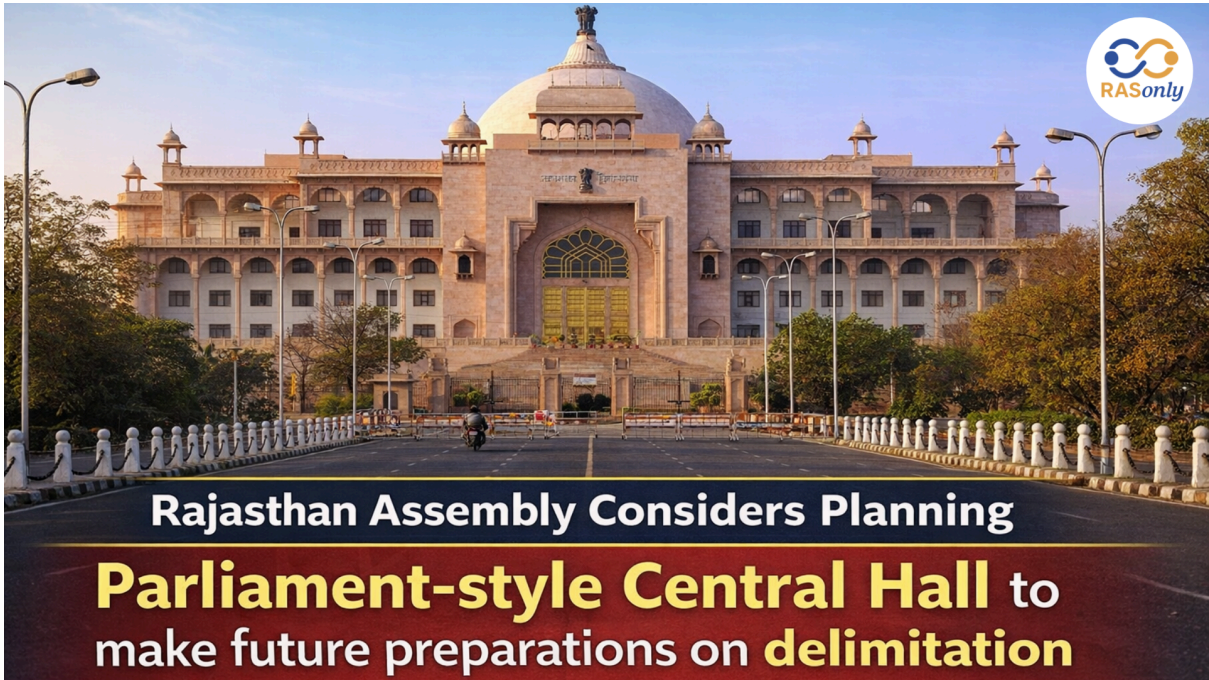


Rajasthan Assembly Considers Planning Parliament-style Central Hall to make future preparations on delimitation.



The Rajasthan Legislative Assembly is undergoing a redesign to address future institutional requirements particularly with the potential delimitation exercise after 2026. The fifth floor of the Assembly building will contain a Parliament-like Central Hall, and the project will aim at modernising the complex but retain the artistic and cultural identity of Rajasthan. The planning takes into account a possible increase in Assembly seats from 200 to 270. Therefore, they are preparing seating arrangements of up to 282 members. The project will also focus on enabling the Assembly to be more technologically savvy, culturally diverse and efficient in its administration.

The main characteristics of the proposed Central Hall include:

- It is proposed to have a new Central Hall in the fifth floor of the Rajasthan Assembly building.
- It is designed based on the operation pattern of the Parliament complex in New Delhi.
- The project has been designed taking into consideration of a future delimitation beyond 2026.

- Rajasthan: Assembly seats in Rajasthan can be increased by 200 to 270 seats following delimitation.
- Preparation of seating arrangements of 282 members is underway.
- The Assembly building will be modernized with new facilities and better space planning.

Planned Design and Institutional Arrangements.

- There will be separate Aisle and No lobbys, as is the current trend in legislation.
- The sitting arrangement will be more or less similar to that of Parliament.
- Seats of Speaker, Chief Minister, Assembly Secretary and other important functionaries are to be planned in an organised way.
- The design also includes VIP rooms, functional rooms that are separate, waiting areas and larger staff spaces.
- The project aims at enhancing convenience and institutional operations at the Assembly complex.

Technology and Modernisation

- The Assembly is moving to paperless working system.
- The new hall will have technological integration as one of its features.
- The hall will be visualized with features like 3D artistic displays of the historical heritage of Rajasthan.
- The current contemporary tools available to the members will be supplemented with additional enhancement of the tables, equipment, and digital functionality.

Cultural and Architectural Identity.

- The Central Hall will be an Indian art, culture and historical pride.
- It will have an architecture made of Jodhpur and Bansi Paharpur stone.
- Traditional Rajasthani features, including jharokhas and arches will be used.
- There is a likelihood that art styles related to the regions of Shekhawati, Mewar and Marwar will be represented.
- The objective is to make the Assembly complex a not only a legislative area but also a representation of the Rajasthan heritage.

Budget and Timeline

- Previous budget approvals had already been made that was 14 crore to cover construction related works.
- The increased project cost quoted above is approximately 17 crore.
- It is hoped that within approximately one year the change will be noticeable.

- The project is also to be used to facilitate further education and community events within the Assembly premises.

Conclusion

The proposed Central Hall of the Rajasthan Legislative Assembly is not a project involving just an infrastructure but a long term institutional preparation towards future delimitation and expanded legislative capacity. The integration of technology, cultural symbolism and the Parliament-style planning has seen the project being an attempt to develop a modern, efficient and identity-filled legislative space in Rajasthan.

MCQs

1. The proposed Parliament like Central hall in the Rajasthan Legislature assembly is designed on which floor?

- (a) Third floor
- (b) Fourth floor
- (c) Fifth floor
- (d) Ground floor

Answer : (c) Fifth floor.

Explanation: According to the report, the Central Hall new project is being occupied on the fifth floor of the Rajasthan Assembly building as part of a bigger expansion and modernisation program.

2. The expansion plan of the Rajasthan Legislative Assembly has been prepared mainly in view of the possible delimitation after which year?

- (a) 2024
- (b) 2025
- (c) 2026
- (d) 2030

Answer: (c) 2026

Explanation : It is being planned having at the back of the mind the potential exercise of delimitation after 2026 which will raise the number of Assembly seats in Rajasthan.

3. Which of the following characteristics can be related to the proposed new Central Hall of the Rajasthan Assembly?

- (a) Total elimination of cultural aspects.

(b) Rajasthani conventional design and paperless operations.

(c) Using the Assembly as a museum.

(d) Banning lobby arrangements.

Answer : (b) Rajasthani architectural patterns of the past and paperless operation.

Explanation: The project will be a mixture of modern technology and the cultural identity of Rajasthan. It incorporates paperless legislative operations, 3D heritage, and traditional features, such as jharokhas, arches, and local forms of art.

भविष्य के परिसीमन की तैयारी के लिए राजस्थान विधानसभा में संसद की तर्ज पर सेंट्रल हॉल की योजना

राजस्थान विधानसभा को भविष्य की संस्थागत आवश्यकताओं के अनुसार पुनः डिज़ाइन किया जा रहा है, विशेष रूप से 2026 के बाद संभावित परिसीमन को ध्यान में रखते हुए। विधानसभा भवन की पाँचवीं मंजिल पर संसद जैसी शैली का एक सेंट्रल हॉल बनाया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य परिसर को आधुनिक बनाना है, साथ ही राजस्थान की कलात्मक और सांस्कृतिक पहचान को भी सुरक्षित रखना है। योजना इस संभावना पर आधारित है कि विधानसभा सीटों की संख्या 200 से बढ़कर 270 हो सकती है। इसी कारण 282 सदस्यों तक के बैठने की व्यवस्था की तैयारी की जा रही है। यह परियोजना विधानसभा को अधिक तकनीकी रूप से सक्षम, सांस्कृतिक रूप से प्रतिनिधिक और प्रशासनिक रूप से अधिक दक्ष बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण है।

प्रस्तावित सेंट्रल हॉल की प्रमुख विशेषताएँ

- राजस्थान विधानसभा भवन की पाँचवीं मंजिल पर नया सेंट्रल हॉल प्रस्तावित है।
- इसका स्वरूप नई दिल्ली स्थित संसद परिसर की कार्यप्रणाली से प्रेरित है।
- परियोजना की योजना 2026 के बाद संभावित परिसीमन को ध्यान में रखकर बनाई गई है।
- परिसीमन के बाद राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या 200 से बढ़कर 270 हो सकती है।
- 282 सदस्यों के लिए बैठने की व्यवस्था तैयार की जा रही है।
- विधानसभा भवन को आधुनिक सुविधाओं और बेहतर स्थानिक योजना के साथ उन्नत किया जाएगा।

नियोजित संरचना और संस्थागत व्यवस्था

- वर्तमान संसदीय व्यवस्था की तरह अलग-अलग “हाँ” और “ना” लॉबी बनाई जाएँगी।
- बैठने की व्यवस्था व्यापक रूप से संसद जैसी होगी।

- अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, विधानसभा सचिव तथा अन्य प्रमुख पदाधिकारियों के लिए व्यवस्थित स्थान निर्धारित किए जाएंगे।
- योजना में विशिष्ट अतिथि कक्ष, पृथक कार्यात्मक कक्ष, प्रतीक्षा क्षेत्र तथा बड़े कर्मचारी कक्ष भी शामिल हैं।
- इस परियोजना का उद्देश्य विधानसभा परिसर में सुविधा और संस्थागत कार्यकुशलता दोनों को बढ़ाना है।

प्रौद्योगिकी और आधुनिकीकरण

- विधानसभा कागजरहित कार्यप्रणाली की ओर बढ़ रही है।
- नए हॉल में तकनीकी एकीकरण एक महत्वपूर्ण विशेषता होगी।
- हॉल में राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहर को दर्शाने वाली त्रिआयामी कलात्मक अभिव्यक्तियाँ शामिल की जाएंगी।
- सदस्यों के लिए उपलब्ध आधुनिक साधनों को और बेहतर मेजों, उपकरणों तथा डिजिटल कार्यप्रणाली से सुदृढ़ किया जाएगा।

सांस्कृतिक और स्थापत्य पहचान

- सेंट्रल हॉल राजस्थान की कला, संस्कृति और ऐतिहासिक गौरव को प्रतिबिंबित करेगा।
- इसके निर्माण में जोधपुर पत्थर और बंसी पहाड़पुर पत्थर का उपयोग किए जाने की संभावना है।
- पारंपरिक राजस्थानी तत्व जैसे झरोखे और मेहराब इसमें सम्मिलित किए जाएंगे।
- शेखावाटी, मेवाड़ और मारवाड़ जैसे क्षेत्रों से जुड़ी कला शैलियों को भी स्थान दिया जा सकता है।
- उद्देश्य यह है कि विधानसभा परिसर केवल विधायी स्थल न रहकर राजस्थान की विरासत का प्रतीक भी बने।

बजट और समयसीमा

- निर्माण संबंधी कार्यों के लिए पहले ही ₹14 करोड़ की स्वीकृति दी जा चुकी थी।
- उन्नत परियोजना की कुल अनुमानित लागत लगभग ₹17 करोड़ बताई गई है।
- लगभग एक वर्ष के भीतर परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई देने की संभावना है।
- यह परियोजना विधानसभा परिसर में भविष्य के शैक्षिक और सार्वजनिक कार्यक्रमों को भी समर्थन देगी।

निष्कर्ष

राजस्थान विधानसभा का प्रस्तावित सेंट्रल हॉल केवल एक अवसंरचनात्मक परियोजना नहीं है, बल्कि भविष्य के परिसीमन और बढ़ी हुई विधायी क्षमता के लिए दीर्घकालिक संस्थागत तैयारी भी है। प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक प्रतीकात्मकता और संसद जैसी योजना के समन्वय के माध्यम से यह

परियोजना राजस्थान में एक आधुनिक, दक्ष और पहचान-सम्पन्न विधायी परिसर विकसित करने का प्रयास है।

MCQs

1. राजस्थान विधानसभा में प्रस्तावित संसद जैसी शैली का सेंट्रल हॉल किस मंजिल पर बनाया जाना है?

- (a) तीसरी मंजिल
- (b) चौथी मंजिल
- (c) पाँचवीं मंजिल
- (d) भूतल

Answer: (c) पाँचवीं मंजिल

Explanation: समाचार के अनुसार राजस्थान विधानसभा भवन में नया सेंट्रल हॉल पाँचवीं मंजिल पर बनाया जाना प्रस्तावित है। यह योजना विधानसभा के विस्तार और आधुनिकीकरण की व्यापक प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप संस्थागत ढाँचे को सुदृढ़ करना है।

2. राजस्थान विधानसभा के विस्तार की यह योजना मुख्य रूप से किस वर्ष के बाद संभावित परिसीमन को ध्यान में रखकर बनाई गई है?

- (a) 2024
- (b) 2025
- (c) 2026
- (d) 2030

Answer: (c) 2026

Explanation: यह योजना 2026 के बाद संभावित परिसीमन को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही है। माना जा रहा है कि परिसीमन के बाद राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ सकती है, इसलिए अभी से अधिक सदस्यों के बैठने और कार्य करने की व्यवस्था विकसित की जा रही है।

3. निम्नलिखित में से कौन-सी विशेषता राजस्थान विधानसभा के प्रस्तावित नए सेंट्रल हॉल से संबंधित है?

- (a) सांस्कृतिक तत्वों का पूर्णतः निष्कासन
- (b) पारंपरिक राजस्थानी स्थापत्य तत्व और कागजरहित कार्यप्रणाली
- (c) विधानसभा को संग्रहालय में परिवर्तित करना
- (d) लॉबी व्यवस्था को समाप्त करना

Answer: (b) पारंपरिक राजस्थानी स्थापत्य तत्व और कागजरहित कार्यप्रणाली

Explanation: प्रस्तावित परियोजना आधुनिक तकनीक और राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान का समन्वय प्रस्तुत करती है। इसमें कागजरहित विधायी कार्यप्रणाली, ऐतिहासिक धरोहर की त्रिआयामी प्रस्तुति तथा झरोखे, मेहराब और क्षेत्रीय कला शैलियों जैसे पारंपरिक राजस्थानी स्थापत्य तत्वों को शामिल करने की योजना है।

Jaisalmer in Rajasthan Government has made a significant step towards conserving Oran.



Jaisalmer in Rajasthan Government has made a significant step towards conserving Oran.

To maintain the ecological balance and to pay attention to the local community feelings, the Rajasthan Government made a significant step and ordered to preserve the Oran land in Jaisalmer district. Orans are the traditional sacred grove that has been safeguarded over the ages by both social and religious beliefs. Deforestation in such places or use of an axe is believed to be taboo and this has helped preserve the natural ecosystem. The significance of this initiative in the RAS examination terms is the fact that it relates to the environment conservation, the practices of the traditional communities, the biodiversity protection, the desert ecology, and the mission that the state has in the conservation of culturally important landscapes.

The important particulars of the land that was allotted to Oran

A total of 3666.2139 hectares of land has been set aside by the State Government to be used as conservation of Oran in various villages of Jaisalmer district.

Reserved areas include:

In Ramgarh tehsil:

- Dilawar ka Gaon: 124.9502 hectares
- Kuchri: 1084.8043 hectares
- Poonamnagar: 583.9876 hectares

In Fatehgarh tehsil:

- Bhimsar: 952.2752 hectares
- Binjota: 96.7716 hectares

In Jaisalmer tehsil:

mokla three blocks: 187.364 hectares

256.2511 hectares

253.4034 hectares

Birma Kanod: 126.4065 hectares

Other Areas In which Reservation Process is in progress.

In addition to the already reserved land, they are also moving to reserve more land as **Oran in the following areas:**

- Mokla in Jaisalmer tehsil: 1457.4991 hectares
- Nachna tehsil, Askandra: 225.03 hectares.
- Didhu: 229.5067 hectares
- Mohangarh Barani/Pannodharai: 333.9165 hectares

Significance and Meaning of Oran

- Oran is a word that is formed out of the Sanskrit word aranya.
- It refers to a forest that is in its original condition or a naturally preserved wood area.
- Orans are the signs of ancient faith and tradition in the religion.
- They are a mirror of a model of conservation where individuals themselves conserve nature by cultural values and traditional rules.

Ecological and Cultural Significance

Ecological Importance

- Orans are used to aid ecological balance in deserts.
- They aid the vegetation in arid areas.
- They can aid in the conservation of biodiversity.
- They can be handy in monitoring desertification.

Cultural Importance

- Orans are associated with the local religion and traditional beliefs.
- They symbolize the peace of conservation and community feeling.
- They are just some of the ways in which cultural practices can be applied to help in protecting the environment.

Conclusion

The Oran conservation initiative of the Rajasthan Government in Jaisalmer is an important move to preserve sacred landscapes, local traditions and ecology of the desert. The state is enhancing biodiversity conservation, preventing desertification, and maintaining a rich heritage of community-based environmental protection by setting aside large plots of land to Orans. This renders the initiative significant ecologically and administration-wise.

MCOs

1. How much land in the Jaisalmer district has been reserved by the Rajasthan Government to be used in the Oran conservation?

- (a) 2700.2139 hectares
- (b) 3666.2139 hectares
- (c) 1457.4991 hectares
- (d) 225.03 hectares

Answer: (b) 3666.2139 hectares

Explanation: The State Government has conserved a total of 3666.2139 hectares of land in various villages of Jaisalmer district. This has been done to ensure that there is ecological balance as well as to preserve the regions related to the local faith, traditional conservation practices and biodiversity in the desert region.

2. The word "Oran" is derived from which Sanskrit word?

- (a) Aravali
- (b) Arogya
- (c) Aranya
- (d) Archana

Answer: (c) Aranya

Explanation: The word Oran is derived by the Sanskrit word Aranya that means a forest that has not been disturbed. This sense indicates the primitive nature of Orans as traditionally undisturbed natural ecosystems where the cutting and disturbance of trees are socially limited and the local ecosystem is therefore able to endure long durations.

3. Why are Orans valued in the desert regions such as Jaisalmer?

- (a) They are only urban development oriented.

- (b) They promote mining development.
- (c) They can be used to preserve biodiversity and curb desertification.
- (d) They are applied to tourism infrastructure only.

Answer : (c) They aid in the preservation of biodiversity and curb desertification.

Explanation : Orans are significant in desert areas since they conserve the greenery, ensure biodiversity as well as maintaining the balance of the environment. These sacred groves are mostly left undisturbed because of community beliefs, which means that they are a natural conservation area and are useful in ensuring that desertification in the vulnerable arid environments is minimized.

जैसलमेर में ओरण संरक्षण की दिशा में राजस्थान सरकार का महत्वपूर्ण कदम

राजस्थान सरकार ने जैसलमेर जिले में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने और स्थानीय जनभावनाओं का सम्मान करने के उद्देश्य से ओरण भूमि के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ओरण ऐसे पारंपरिक पवित्र उपवन हैं, जिनकी रक्षा सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर पीढ़ियों से की जाती रही है। इन क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई या कुल्हाड़ी का प्रयोग वर्जित माना जाता है, जिससे यहाँ का प्राकृतिक तंत्र सुरक्षित बना रहता है। यह पहल आरएएस परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पर्यावरण संरक्षण, पारंपरिक समुदायों की भूमिका, जैव विविधता, मरुस्थलीय पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थलों के संरक्षण से जुड़ी हुई है।

ओरण के लिए आरक्षित भूमि का विवरण

राज्य सरकार ने जैसलमेर जिले के विभिन्न गाँवों में ओरण संरक्षण हेतु कुल 3666.2139 हैक्टेयर भूमि आरक्षित की है।

आरक्षित क्षेत्र इस प्रकार हैं:

- रामगढ़ तहसील में:
 - दिलावर का गाँव: 124.9502 हैक्टेयर
 - कुछड़ी: 1084.8043 हैक्टेयर
 - पूनमनगर: 583.9876 हैक्टेयर
- फतेहगढ़ तहसील में:
 - भीमसर: 952.2752 हैक्टेयर
 - बीजोता: 96.7716 हैक्टेयर

- जैसलमेर तहसील में:
 - मोकला के तीन अलग-अलग खंड:
 - 187.364 हैक्टेयर
 - 256.2511 हैक्टेयर
 - 253.4034 हैक्टेयर
 - बीरमा काणोद: 126.4065 हैक्टेयर

जिन क्षेत्रों में आरक्षण की कार्यवाही जारी है

पहले से आरक्षित भूमि के अतिरिक्त निम्न क्षेत्रों को भी ओरण के रूप में आरक्षित करने की कार्यवाही की जा रही है:

- मोकला (जैसलमेर तहसील): 1457.4991 हैक्टेयर
- आसकन्द्रा (नाचना तहसील): 225.03 हैक्टेयर
- दिधू: 229.5067 हैक्टेयर
- मोहनगढ़ बारानी/पन्नोधराय: 333.9165 हैक्टेयर

ओरण का अर्थ और महत्व

- ओरण शब्द संस्कृत के अरण्य शब्द से बना है।
- इसका अर्थ है अछूता वन या प्राकृतिक रूप से सुरक्षित वन क्षेत्र।
- ओरण प्राचीन धार्मिक परंपराओं और सामुदायिक आस्था के प्रतीक हैं।
- ये ऐसे संरक्षण मॉडल को दर्शाते हैं, जिसमें लोग अपनी सांस्कृतिक मान्यताओं और परंपरागत नियमों के आधार पर स्वयं प्रकृति की रक्षा करते हैं।

पारिस्थितिक और सांस्कृतिक महत्व

पारिस्थितिक महत्व

- ओरण मरुस्थलीय क्षेत्रों में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में सहायक हैं।
- ये शुष्क क्षेत्रों में हरियाली को बनाए रखने में मदद करते हैं।
- ये जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- ये मरुस्थलीकरण को रोकने में उपयोगी हैं।

सांस्कृतिक महत्व

- ओरण स्थानीय आस्था और पारंपरिक मान्यताओं से जुड़े हुए हैं।
- ये संरक्षण और जनभावनाओं के समन्वय का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।

- ये दिखाते हैं कि सांस्कृतिक परंपराएँ भी पर्यावरण संरक्षण का सशक्त माध्यम बन सकती हैं।

निष्कर्ष

जैसलमेर में ओरण संरक्षण के लिए राजस्थान सरकार की यह पहल पवित्र स्थलों, स्थानीय परंपराओं और मरुस्थलीय पारिस्थितिकी की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ओरण के लिए बड़े भू-भाग को आरक्षित करके राज्य जैव विविधता संरक्षण को मजबूत कर रहा है, मरुस्थलीकरण को रोकने में सहायता दे रहा है और समुदाय आधारित पर्यावरण संरक्षण की समृद्ध विरासत को संरक्षित कर रहा है। इसलिए यह पहल पर्यावरणीय और प्रशासनिक दोनों दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

MCQs

1. राजस्थान सरकार ने जैसलमेर जिले में ओरण संरक्षण के लिए कितनी भूमि आरक्षित की है?
- (a) 2700.2139 हैक्टेयर
(b) 3666.2139 हैक्टेयर
(c) 1457.4991 हैक्टेयर
(d) 225.03 हैक्टेयर

उत्तर: (b) 3666.2139 हैक्टेयर

व्याख्या: राज्य सरकार ने जैसलमेर जिले के विभिन्न गाँवों में कुल 3666.2139 हैक्टेयर भूमि ओरण संरक्षण के लिए आरक्षित की है। यह कदम पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने, स्थानीय आस्था से जुड़े क्षेत्रों की रक्षा करने, पारंपरिक संरक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा मरुस्थलीय क्षेत्र की जैव विविधता को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।

2. "ओरण" शब्द किस संस्कृत शब्द से बना है?

- (a) अरावली
(b) आरोग्य
(c) अरण्य
(d) अर्चना

उत्तर: (c) अरण्य

व्याख्या: "ओरण" शब्द संस्कृत के "अरण्य" शब्द से बना है, जिसका अर्थ अछूता वन होता है। यह अर्थ ओरण की मूल प्रकृति को स्पष्ट करता है, क्योंकि ऐसे क्षेत्र पारंपरिक रूप से संरक्षित प्राकृतिक स्थल होते हैं, जहाँ पेड़ों की कटाई और मानवीय हस्तक्षेप पर सामाजिक नियंत्रण होता है, जिससे स्थानीय पारिस्थितिकी लंबे समय तक सुरक्षित बनी रहती है।

3. जैसलमेर जैसे मरुस्थलीय क्षेत्रों में ओरण क्यों महत्वपूर्ण माने जाते हैं?

- (a) वे केवल शहरी विकास के लिए बनाए जाते हैं
(b) वे खनन विस्तार को बढ़ावा देते हैं
(c) वे जैव विविधता संरक्षण और मरुस्थलीकरण को रोकने में सहायक हैं
(d) वे केवल पर्यटन अवसंरचना के लिए उपयोगी हैं

उत्तर: (c) वे जैव विविधता संरक्षण और मरुस्थलीकरण को रोकने में सहायक हैं

व्याख्या: ओरण मरुस्थलीय क्षेत्रों में इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे हरियाली को बनाए रखते हैं, जैव विविधता की रक्षा करते हैं और पारिस्थितिकी संतुलन को मजबूत करते हैं। सामुदायिक मान्यताओं

के कारण ये पवित्र उपवन प्रायः बिना छेड़छाड़ के सुरक्षित रहते हैं, जिससे वे प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र के रूप में कार्य करते हैं और शुष्क क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण को कम करने में सहायक बनते हैं।

Rajasthan celebrates the 77th Police Establishment Day with emphasis on Safer Governance and Bigger Policing.

RAJASTHAN CELEBRATES THE 77TH POLICE ESTABLISHMENT DAY
with emphasis on Safer Governance and Bigger Policing.



The Rajasthan Government took the opportunity of the 77 th Rajasthan Police Establishment Day to emphasize its observance of law and order, zero tolerance to corruption and safe environment of the citizens. Speaking at the state-level event at the Rajasthan Police Academy, Chief Minister Bhajanlal Sharma claimed that the Rajasthan Police has been instrumental in the provision of security to the people by instilling discipline, devotion and service. The significance of the event in the context of RAS examination is that it has bridged internal security, police reforms, control of

cybercrime, anti-narcotics control, institutional strengthening and welfare of the police personnel.

Event Highlights

- The Chief Minister was present at the state-level event celebrating the 77th anniversary of the Rajasthan Police Establishment Day.
- He visited the ceremonial parade and honored martyrs in the martyr memorial.
- The Chief Minister also awarded Police officers with the Excellence Service Medal.
- Retired police were provided with a new portal and mobile app.
- The Chief Minister said that the government is determined to create a crime-free Rajasthan by adopting a zero-tolerance attitude towards corruption and crime.

The Crime Control and Law-and-Order Outcomes

According to the government, crime in Rajasthan is reduced by 18.77 percent in the previous two years. The announcements at the event stated that there was a reduction in cases of murder by 25.68 percent, dacoity by 47.26 percent, robbery by 50.75 percent and crimes against women by an approximate of 10 percent. These numbers were brought out as the result of tighter law enforcement, the policing in the modern times and the targeted administrative intervention.

Community Policing and Action Against New-Age Crime

- The Chief Minister mentioned that society and police complement each other.
- He emphasised that community policing has the potential to address cybercrime, drug abuse and organised crimes.
- As part of raising awareness and curbing cyber crimes, all police stations have set up cyber help desks.
- Action by anti-Narcotics task force has resulted in one police station and 17 police outposts.
- An SIT was constituted against the cheating mafia and it was said that there was not even a single leakage of papers in the state at this time.
- The Anti-Gangster Task Force is also striving to tame organised crime and minimise the number of deaths associated with the use of firearms.

Measures to reform Rajasthan Police

- Over 8,000 constables have received appointment letters.
- It has brought about 2 other Superintendent of Police offices, 2 Deputy Superintendent of Police offices and 23 new police stations.
- 8 police outposts have been transformed into police stations.

- 1,000 police mobile units deployed.
- 35 new police posts have been opened.
- Annual uniform allowance between constable to assistant sub-inspector level has been raised.
- Mess allowance of police personnel is also raised.

Promotions by the Chief Minister

- The plan to train more police was announced by building of the following:
- 5 crore more was declared to the sports fund, welfare fund and festival fund of police personnel.
- At the initial stage, the construction of 500 houses to house police officers of various categories was also declared.

Conclusion

The 77th Rajasthan Police Establishment Day was to celebrate not just the police service, police sacrifice, but a wider conception of governance through modernisation, welfare, accountability, and citizen involvement. The publicity and statistical reports on the performance in the event render it a significant topic of current affairs in RAS preparation, particularly in the spheres of internal security, the rule of law, police reforms, and the administration of the population.

MCOs

1. How did the overall crime reduction in Rajasthan reduce in the past two years according to the announcements made on Rajasthan Police Establishment Day?

- (a) 10.00 percent
- (b) 18.77 percent
- (c) 25.68 percent
- (d) 50.75 percent

Answer: (b) 18.77 percent

Explanation: According to the Chief Minister, the general crime in Rajasthan reduced by 18.77 percent over the past two years. This statistic was given as the outcome of tougher law enforcement, zero-tolerance rule, institutional reforms, and specific action against organised crime, cybercrime and corruption.

2. Which of the following measures was specifically highlighted as a tool to tackle cybercrime in Rajasthan?

- (a) Establishment of a tourism development board.
- (b) creation of cyber help desks in every police station.

- (c) Development of district environment councils.
- (d) The new transport sub way subsidy scheme.

Answer : (b) Cyber help desks to be set up in every police station.

Explanation: The event has brought out the fact that cyber help desks have been established in every police station in Rajasthan. The suggested measure is supposed to enhance awareness of the population, enhance cybercrime response, and assist citizens in addressing the ever-increasing digital threats systematically and conveniently.

3. Which among the following announcements were made in the interest of welfare and capacity development of the Rajasthan Police personnel?

- (a) 50 new universities to be opened.
- (b) Creation of a new legislative council
- (c) 5 barracks with 100 persons each to be constructed in training institutions.
- (d) New export zones.

Answer: (c) Building of 5 barracks with a 100-person capacity each in training institutions.

Explanation : The Chief Minister declared that there would be five barracks of a capacity of 100 persons in the various police training institutions. This move is done in order to enhance the police training capacity and indicates the interest of the state government in the modernisation of the police, their welfare and strengthening their institutions.

राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस, कानून-व्यवस्था सुधार, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था और पुलिस आधुनिकीकरण

राजस्थान सरकार ने 77वें राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर कानून-व्यवस्था, भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता और नागरिकों के लिए सुरक्षित वातावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान पुलिस ने अनुशासन, समर्पण और जनसेवा की भावना के साथ आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आरएस परीक्षा की दृष्टि से यह विषय महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आंतरिक सुरक्षा, पुलिस सुधार, अंतरजालीय अपराध नियंत्रण, मादक पदार्थ निरोधक कार्रवाई, संस्थागत सुदृढीकरण और पुलिस कर्मिकों के कल्याण से जुड़ा हुआ है।

कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएँ

- मुख्यमंत्री ने 77वें राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में भाग लिया।
- उन्होंने सेरेमोनियल परेड का निरीक्षण किया और शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की।
- पुलिस कार्मिकों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया।
- सेवानिवृत्त पुलिस कार्मिकों के लिए नया डिजिटल मंच और चलदूरभाष अनुप्रयोग प्रारंभ किया गया।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार और अपराध के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति अपनाकर अपराधमुक्त राजस्थान के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है।

अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था की स्थिति

सरकार के अनुसार पिछले दो वर्षों में राजस्थान में कुल अपराधों में **18.77 प्रतिशत** की कमी आई है। कार्यक्रम में साझा किए गए आँकड़ों के अनुसार हत्या के मामलों में **25.68 प्रतिशत**, डकैती में **47.26 प्रतिशत**, लूट में **50.75 प्रतिशत** तथा महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में लगभग **10 प्रतिशत** की कमी दर्ज की गई है। इन उपलब्धियों को कठोर कानून-प्रवर्तन, आधुनिक पुलिस व्यवस्था और लक्षित प्रशासनिक कार्रवाई का परिणाम बताया गया।

सामुदायिक पुलिस व्यवस्था और नवीन प्रकार के अपराधों पर नियंत्रण

- मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस और समाज एक-दूसरे के पूरक हैं।
- उन्होंने रेखांकित किया कि सामुदायिक पुलिस व्यवस्था के माध्यम से अंतरजालीय अपराध, नशा और संगठित अपराध जैसी चुनौतियों का प्रभावी सामना किया जा सकता है।
- सभी पुलिस थानों में अंतरजालीय सहायता कक्ष स्थापित किए गए हैं, ताकि जनजागरूकता बढ़े और ऐसे अपराधों पर नियंत्रण हो।
- मादक पदार्थ निरोधक कार्यबल की कार्रवाई के अंतर्गत 1 पुलिस थाना और 17 पुलिस चौकियाँ स्थापित की गई हैं।
- नकल माफिया के विरुद्ध विशेष जांच दल का गठन किया गया तथा इस अवधि में राज्य में एक भी प्रश्नपत्र लीक न होने की बात कही गई।
- अपराधी गिरोह निरोधक कार्यबल भी संगठित अपराध पर अंकुश लगाने और आग्नेयास्त्रों के उपयोग से होने वाली मौतों को कम करने के लिए सक्रिय है।

राजस्थान पुलिस को सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए कदम

- **8,000 से अधिक आरक्षियों** को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं।
- **2 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय**, **2 उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय** तथा **23 नए पुलिस थाने** स्थापित किए गए हैं।
- **8 पुलिस चौकियों** को पुलिस थानों में क्रमोन्नत किया गया है।
- **1,000 पुलिस चल इकाइयाँ** तैनात की गई हैं।

- 35 नई पुलिस चौकियाँ खोली गई हैं।
- आरक्षी से सहायक उपनिरीक्षक स्तर तक वार्षिक वर्दी भत्ते में वृद्धि की गई है।
- पुलिस कार्मिकों के भोजनालय भत्ते में भी बढ़ोतरी की गई है।

मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाएँ

- पुलिस प्रशिक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में 100-100 व्यक्तियों की क्षमता वाली 5 बैरकों के निर्माण की घोषणा की गई।
- पुलिस कार्मिकों के क्रीड़ा, कल्याण और उत्सव निधि के लिए ₹5 करोड़ के अतिरिक्त प्रावधान की घोषणा की गई।
- प्रथम चरण में विभिन्न श्रेणियों के पुलिस कार्मिकों के लिए 500 आवासों के निर्माण की भी घोषणा की गई।

निष्कर्ष

77वाँ राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस केवल पुलिस सेवा और बलिदान के सम्मान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह आधुनिककरण, उत्तरदायित्व, कल्याण और जनभागीदारी पर आधारित व्यापक शासन-दृष्टि को भी सामने लाया। कार्यक्रम में साझा की गई घोषणाएँ और उपलब्धियाँ इसे आरएएस की दृष्टि से आंतरिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था, पुलिस सुधार और लोक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण समसामयिक विषय बनाती हैं।

MCQs

1. राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस समारोह में साझा किए गए आँकड़ों के अनुसार, पिछले दो वर्षों में राजस्थान में कुल अपराधों में कितनी कमी आई?

- (a) 10.00 प्रतिशत
- (b) 18.77 प्रतिशत
- (c) 25.68 प्रतिशत
- (d) 50.75 प्रतिशत

उत्तर: (b) 18.77 प्रतिशत

व्याख्या: मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दो वर्षों में राजस्थान में कुल अपराधों में 18.77 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। इसे कठोर कानून-प्रवर्तन, भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता, संस्थागत सुधारों तथा संगठित अपराध, अंतरजालीय अपराध और भ्रष्टाचार के विरुद्ध लक्षित कार्रवाई का परिणाम बताया गया।

2. राजस्थान में अंतरजालीय अपराधों से निपटने के लिए विशेष रूप से किस उपाय को रेखांकित किया गया?

- (a) पर्यटन विकास मंडल की स्थापना
- (b) सभी पुलिस थानों में अंतरजालीय सहायता कक्ष की स्थापना
- (c) जिला पर्यावरण परिषदों का गठन
- (d) नई परिवहन अनुदान योजना का शुभारंभ

उत्तर: (b) सभी पुलिस थानों में अंतरजालीय सहायता कक्ष की स्थापना

व्याख्या: समारोह में यह विशेष रूप से बताया गया कि राजस्थान के सभी पुलिस थानों में अंतरजालीय सहायता कक्ष स्थापित किए गए हैं। इस कदम का उद्देश्य जनजागरूकता बढ़ाना, अंतरजालीय अपराधों के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया को मजबूत करना और नागरिकों को बढ़ते डिजिटल खतरों से व्यवस्थित रूप से निपटने में सहायता देना है।

3. राजस्थान पुलिस कार्मिकों के कल्याण और क्षमता विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी घोषणा की गई?

(a) 50 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना

(b) नए विधान परिषद का गठन

(c) प्रशिक्षण संस्थानों में 100 व्यक्तियों की क्षमता वाली 5 बैरकों का निर्माण

(d) नए निर्यात क्षेत्रों की स्थापना

उत्तर: (c) प्रशिक्षण संस्थानों में 100 व्यक्तियों की क्षमता वाली 5 बैरकों का निर्माण

व्याख्या: मुख्यमंत्री ने विभिन्न पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में 100-100 व्यक्तियों की क्षमता वाली 5 बैरकों के निर्माण की घोषणा की। यह कदम पुलिस प्रशिक्षण क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है और इससे स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार पुलिस आधुनिकीकरण, कार्मिक कल्याण और संस्थागत सुदृढीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है।